बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में स्कूल बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों को तथा उन बच्चों को जो पूरे दिन स्कूलों में नहीं जा सकते औपचारिक पद्धति के तुलनीय कोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के रूप में छठी पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी। इस योजना का अरुणाचल प्रदेश तथा अन्य सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कामकाज करने वाले बहुत बच्चों वाले क्षेत्रों तथा शहरी गन्दी बस्तियों, पर्वतीय, रेगिस्तानी और जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार तथा पुनर्गठन किया गया।

राज्य सरकारों को सह शिक्षा और लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों को चलाने के लिए क्रमशः 50:50 और 90:10 के अनुपात में इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जा रही है; स्वैच्छिक एजेंसियों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में स्वायत्तशासी कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आवंटित की गई धनराशि

2866. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्वायत्तशासी कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी. शिव शंकर): उत्तर प्रदेश के किसी कालेज को अभी तक स्वायत्त स्तर प्रदान नहीं किया गया है। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निधियों के आवंटन का प्रश्न नहीं उठता है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य

2867. **श्री राम जेठमलानी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य क्या हैं;

(ख) यदि हां, तो इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त धन लेने के लिए योजना आयोग से मंजूरी ले ली है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंधी ब्यौरा क्या है और इस धनराशि को प्राप्त करने के लिए सरकार का किन-किन स्रोतों से धन लेने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी. शिवशंकर): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ा किया जाना

2868. **श्री अजीत जोगी:**
ठाकुर जगतपाल सिंह:

क्या जल-यूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या हैं जिन्हें चार-लेन वाले राजमार्गों में बदलने का कार्य हाथ में लिया गया है;

(ख) उस कार्य के लिए पिछले तीन वर्षों में कितनी धनराशि आवंटित

की गई है और इसी अवधि में उसमें से कितनी उपलब्ध करायी गई है ;

(ग) इसी कार्य के लिए मध्य प्रदेश की तुलना में अन्य राज्यों को कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) अभी तक मध्य प्रदेश में चार लाइनों के राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई भी कार्य आरम्भ नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) एकीकृत रूप में सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए राशि का आवंटन राज्यों को वर्ष प्रति वर्ष किया जाता है वर्तमान में, मध्य प्रदेश को छोड़कर विभिन्न राज्यों में राजमार्गों के लिए लगभग 332 करोड़ रुपयों की स्वीकृत लागत के चार लाइनों के कार्य प्रगति पर है।

(घ) वर्तमान वित्त वर्ष में चार लाइनों पर अब तक खर्च की गई परिशुद्ध राशि उपलब्ध नहीं है ।

इलाहाबाद में यमुना नदी पर पुल बनाने की योजना

2869. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद में यमुना नदी पर पुल बनाने की योजना का ब्यौरा क्या है तथा उसके निर्माण के संबंध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या पुल का शिलान्यास कर दिया गया है, यदि हां, तो वह किसने किया था ; और

(ग) उस पर कार्य आरम्भ न करने के क्या कारण है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) वर्तमान रेल-व-सड़क पुल से पानी के बहाव की ओर एक 4 लेन वाले पुल के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है जिसे तभी संस्वीकृति दी जा सकती है जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कर ली जाएगी और वह निर्माण की लागत का हिस्सा वहन करने की स्वीकृति की सूचना दे देगी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उपयुक्त (क) और (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

Establishment of SPDA

2870. SHRI SURENDRA SINGH THAKUR: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have adopted any scheme for establishment of Sports Project Development Area;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether Government have established SPDA Centres in Madhya Pradesh; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) Yes, Sir.

(b) Under this Scheme, the existing sports infrastructure in selected District Headquarters is to be upgraded by the creation of Sports Project Development Area Centres which will